श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब के एसैट्स एंड लायबिलिटीज के बंटवारे का आधार नये प्रदेशों की पापुलेशन होगा या एरिया ।

श्री नन्दा : इस सम्बन्ध में पहले कुछ नियम बन चुके हैं । अगर आप कहें, तो मैं उन नियमों को पढ़ दूं, लेकिन इस में समय लगेगा । वही नियम इस कानून में दाखिल किये जायेंगे ।

Shri Hem Barua: President's rule in Punjab is going to end on 2nd October, 1966 and it has been reported in the papers that the decision whether to extend the President's rule in Punjab or not would be taken after the Congress President comes back from the Soviet Union. In this connection, may I know (a) whether the Government have decided to extend the President's rule in Punjab after its termination and (b) whether it is the Indian Government under the leadership of the Prime Minister who takes decisions in such matters or it is the Congress Party and Congress President?

Mr. Speaker: This does not arise out of this question. The main question is about financial assets and liabilities that are to be divided.

Shri Hem Barua: President's rule is relevant because . . .

Mr. Speaker: That question has been put by Mr. Shastri already and answered.

Shri D. C. Sharma: There are some Central Government projects which were the joint property of Kangra, Himachal Pradesh, Punjabi Suba as it is now called and Haryana Prant. Will they continue to be run by the Central Government or will those assets and liabilities also be divided between the new regions? Forests worth Rs. 200 crores have been taken away from Punjab and given over to Himachal Pradesh, for which I am not very sorry. May I know if the Government is going to make good that loss which is going to accrue to the Punjab?

Shri Nanda: I have already said that the division of assets and liabilities is determined by certain principles.

Mr. Speaker: I agree with him. Next question.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बड़ा अहम सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले सवाल पर चला गया हूं ।

श्री बागड़ी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त और पंजाबी सूबे की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण क्या सरकार हरियाणा प्रान्त की राजधानी कुरुक्षेत्र और पंजाबी सूबे की राजधानी आनन्दपुर साहब बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि दोनों प्रदेशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध बने रहें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन पटनायक ।

Job Security in Oil Companies

\+

*215. **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:
Shri Bagri:
Shri Warior:
Shri Yashpal Singh:
Dr. Ranen Sen:
Shri P. C. Borooah:
Shri A. K. Gopalan:
Shri Dasaratha Deb:
Shri M. N. Swamy:
Shri Dinen Bhattacharya:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shri M. Rampure:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Jashvant Mehta:
Shri C. K. Bhattacharyya:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1615 on the 11th May, 1966 and state:

(a) whether Government have taken any action on the report of

the Chairman of the Tripartite Committee on job Security in Oil Industry;

(b) whether the closing down of can manufacturing units has affected its production and also proper distribution of oil products;

(c) whether any people have since been retrenched; and

(d) if so, the action taken to prevent that?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes. A copy of the Government Resolution on the Subject is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-6635/66].

(b) The closure of the can manufacturing units does not appear to have affected the proper distribution of oil products.

(c) No complaints of any retrenchment have been received. The matter, however, is within the jurisdiction of the State Governments.

(d) Does not arise.

श्री किशन पटनायक : त्रिपक्षीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पिछले पांच छः साल के अन्दर बर्माशैल इस्सो और काल्टैक्स कम्पनियों के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 31 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 18 प्रतिशत घटी है । क्या सरकार बता सकती है कि इस में से कितनी छंटनी इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर्ज के कारण से हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : उस की एग्जेक्ट तादाद तो मुझे मालूम नहीं है , लेकिन वह बहुत ही कम है । आयल कम्पनीज के कहने के मुताबिक कम्प्यूटर्ज की वजह से कोई भी रिट्रेंचमेंट नहीं हुई है ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी उपमंत्री महोदय ने कहा कि वह सही आंकड़े नहीं दे सकते । इस का मतलब यह है कि ऐसे लोगों के कुछ आंकड़े हैं, जो कम्प्यूटर्ज की वजह से प्रभावित हुए हैं । उपमंत्री महोदय ने फिर कहा कि छंटनी नहीं हुई है । उपमंत्री महोदय यह कैसे जवाब देते हैं ।

श्री बागड़ी : उन को जवाब नहीं आता है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने दोनों बातें कही हैं—पहले उन्होंने कहा कि उन के पास ठीक आंकड़े मौजूद नहीं हैं और फिर कहा कि कम्प्यूटर्ज की वजह से कोई रिट्रेंचमेंट नहीं हुई है ।

श्री शाहनवाज खां : मैं ने कहा है कि आयल कम्पनीज के कहने के मुताबिक कम्प्यूटर्ज की वजह से कोई रिट्रेंचमेंट नहीं हुई है ।

श्री मधु लिमये : सरकार उन के कहने पर जा रही है । क्या सरकार ने स्वयं कोई जांच की है ? अगर नहीं की है , तो यह मंत्री और मंत्रालय काहे के लिए हैं ? जहां तक आयल कम्पनियों के कहने का प्रश्न है, उन के अपने पब्लिक रिलेशन्ज आफिस तो हैं ही । अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह रोजगार मंत्रालय है या आयल कम्पनियों का पब्लिक रिलेशन्ज आफिस है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । क्या गवर्नमेंट अपने सींस से कोई इन्फर्मेशन दे सकती है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं एक बात का खुलासा कर देना चाहता हूं । जैसा कि उप-

मंत्री ने अपने जवाब में बताया है, तेल कम्पनियों में यह जो झगड़ा पैदा हुआ है, यह स्टेट गवर्नमेंटस के क्षेत्र में है। इसलिये हम यह दावा नहीं कर सकते कि इस सम्बन्ध में जितनी जानकारी है, वह सब हमारे पास है। जब कभी मौका आता है, तो दिल्ली के अलावा, स्टेट्स की सरकारें जो जानकारी हासिल करती हैं, वह जानकारी हम को मिलती है। इसीलिये उपमंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि यह विषय स्टेट गवर्नमेंट्स के क्षेत्र में पड़ता है। माननीय सदस्य, श्री किशन पटनायक, का प्रश्न था कि कितने लोगों का रिट्रेंचमेंट हुआ। खास तौर से उन्हों ने पूछा कि कम्प्यूटर्ज की वजह से कितने लोगों का रिट्रेंचमेंट हुआ। उपमंत्री ने जवाब दिया कि इस की पूरी जानकारी नहीं है और आयल कम्पनियों के कहने के अनुसार कम्प्यूटर्ज की वजह से कोई छंटनी नहीं हुई है। मैं नहीं समझता कि उस में कोई भी विरोधाभास है। यह बिल्कुल सही जवाब है।

श्री बागड़ी : इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री जगजीवन राम : अभी मैं ने खत्म नहीं किया है।

जैसा कि इस विवरण में बताया गया है, हमने ऐसा इन्तजाम किया कि एक त्रिदलीय कमेटी बैठी और उसमें ऐसा कुछ निर्णय लिया गया कि जब कभी लोगों को पेंशन दे कर समय से पहले हटाने का प्रश्न आये, तो यूनियन के साथ समझौता कर के वह काम अमल में लाया जाये। दिल्ली के अलावा जहां कहीं इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा होगा, तो उसका सीधा सरोकार केन्द्र से नहीं होगा, बल्कि वहां की राज्य सरकार से होगा। लेकिन वहां भी जब कभी ऐसा प्रश्न आता है, तो मैं उस मसले के सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्ध स्थापित करता हूं और उस को देखता हूं। जहां कहीं भी मुझे ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई विशेष रूप से छंटनी हो रही है, तो मैं जरूर उसमें दखल दूंगा।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Dr. Ranen Sen: On a point of order, Sir. In the last session some of us had raised this question. The Government got sufficient time to get this information from the State Governments. Is it permissible for the Minister to get up and say that all this material and information has not been available from the State Government? I want your ruling on this point.

श्री मधु लिमये : इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह राज्य का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "श्रम" का विषय राज्य का भी है और केन्द्र का भी है। आप संविधान को देख लीजिए। और पट्रोलियम का विषय महज केन्द्र का है, राज्य का नहीं है। इसलिये इस बारे में मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है। वह कहते हैं कि कम्पनियों के कथनानुसार इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर्ज की वजह से कोई छंटनी नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मंत्रालय है या पट्रोलियम कम्पनियों का पब्लिक रिलेशन्ज आफिस है।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ठीक इन्फ़र्मेशन तो उनके पास नहीं है, लेकिन कम्पनियों के कहने के मुताबिक कोई छंटनी नहीं हुई है।

श्री मधु लिमये : वह कम्पनियों का एड्वरटाइज़मेंट क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह दोनों बातें कह रहे हैं।

Dr. Ranen Sen: In the last session this question was raised.

Mr. Speaker: I have heard him.

Dr. Ranen Sen: They avoided this question.

Mr. Speaker: Now he should sit down.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, हम ने इस प्रश्न का नोटिस मई में दिया था।

Dr. Ranen Sen: What is your ruling? Is the Minister permitted to avoid this question like this over and over again?

Mr. Speaker: He wanted to stand up but another Member just put that question.

12.00 hrs.

Shri Bhagwat Jha Azad: Sir, on this point of order I would like to say that what the hon. Minister has said is correct from this angle, namely, if it is taken only from the aspect of individual retrenchment of labour, of course, from the Labour Ministry's point of view it looks that it is a State subject; but what we are contending in this House, not today but for years, is that the foreign oil companies are persistently following a policy of squeezing out the Indians who are there on the pretext that they are just old or that they themselves want to go out. The point is that since oil falls in the Central Government's purview and, these companies are trying to squeeze out the Indians in a planned way in the name that they do not want it, it falls within the purview of the Central Government. It is not just one or two instances in a State but it is a general policy which affects the whole country and the Government has accepted that by appointing a committee. Therefore, it should be answered . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: Dr. Ranen Sen has raised the point that last time also it was said by Government that they were getting that information from the State Governments, that there was enough time to get that information; why has that information not been obtained even by now?

Shri Jagjivan Ram: So far as this question is concerned, the answer has been given; it is in respect of the supplementary that the reply has been given that we do not have complete information so far as retrenchment is concerned. But I may add one thing more. If there is any sizable retrenchment, it is not only the oil companies but the trade unions also make an agitation and bring that to our notice. I am not speaking on facts or statistics before me but as an inference, still no trade union has taken up this question of any large-scale retrenchment with the Labour Ministry as such. Whatever agitation has been raised has been raised on the particular clause, not relating to retrenchment but relating to premature retirement with certain enhanced benefits. That also has not been on any large scale.

So far as the question of my hon. friend, Shri Bhagwat Jha Azad, is concerned, he has raised a separate question of squeezing out of Indians. The question of squeezing out of Indians from foreign firms comes only at the top level and if it is a question of squeezing out of Indians at the top level, that will be a category of officials which will be beyond the scope of the Labour Ministry as such. I am not proposing to shirk the responsibility of the Government as such, but so far as the Labour Ministry is concerned, if it is a question affecting the high officials, who will not be covered by the definition of employees or workmen, that will be beyond the scope of the Labour Ministry.

Mr. Speaker: Question Hour is over . . . (*Interruption*).

Dr. Ranen Sen: Mr. Speaker, I may just make a submission.

Mr. Speaker: I cannot continue in this manner . . . (*Interruption*).

Dr. Ranen Sen: There was a tripartite committee under the presidentship of Shri R. L. Mehta, who was a Joint Secretary of the Labour Department. Instead of accepting that committee's report, the Government distored its recommendation as a result of which all these employees will be made redundant and will be at the sweet will of the employers.

Shri Jagjivan Ram: I contradict that statement; that is a mis-statement.

Dr. Ranen Sen: Is it the way the Labour Ministry is going to function? The Labour Ministry's own committee's report has not been accepted . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: The Member might take it up in some other manner.

An hon. Member: The committee's report should be placed on the Table of the House.

Shri Hem Barua: *rose*—

Mr. Speaker: Shri Hem Barua has written to me that question No. 216 be taken up after the Question Hour. It is only the Minister's privilege. If he wants to answer, I can take it up.

Shri Hem Barua: I request the Minister to give a reply.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। एक तो आप पीछे बैठने वालों को चाहे उन के दल की ही कोई बात कहता हो बोलने नहीं देते और व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं उठेगा तो हम कोई बात कह नहीं सकेंगे। बार बार आप देखते हैं कि सदन में माननीय उपमंत्री महोदय जितने प्रश्नों का जवाब देते हैं वह या तो सही नहीं होते या नामुक्कमिल होते हैं। रोज उनके प्रश्नों में यह बात होती है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप के कोई अक्तियार ऐसे गलत मंत्रियों के बारे में हैं या नहीं और अगर हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने इस मंत्रालय को इस बारे में कुछ लिखा या कहा है?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को जो अख्तियार हैं वह भी सारे मेम्बरों को मालूम हैं। मेरे पास कोई अलाहिदा अख्तियार नहीं कि जो मुझे ही मालूम हैं और मेम्बरों को नहीं मालूम हैं और जो हाउस के अख्तियार हैं वह भी आप जानते हैं। आलरेडी नो कांफिडेंस मोशन चल रहा है। आप उस पर ज्यादा जोर दीजिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूं?

श्री बागड़ी : आप हटा नहीं सकते?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं हटा सकता।

Shri Priya Gupta: I have got a submission to make.

Mr. Speaker: Shri Gopalan.

Shri Priya Gupta: I have given a Call Attention notice.

Mr. Speaker: I am not taking up Call Attention notices. I am taking up the Short Notice Question. Shri Gopalan.

Shri Hem Barua: What has happened to my request?

Mr. Speaker: He is not asking for that. What should I do? The Minister only can ask for that. Hence forward, I have taken the decision that the Short Notice Question be printed and circulated to the Members.

Shri Vasudevan Nair: Where is Mr. Sanjiva Reddy? Yesterday, he promised that he will be in the House to answer this Short Notice Question. It is very strange. He absents himself from the House. What has happened to him?

Mr. Speaker: I will take it up separately. Let this Question be answered.

Shri Vasudevan Nair: It is an affront to the Chair.

Mr. Speaker: I am told he is in the Rajya Sabha. He will be coming. Shri Gopalan.

SHORT NOTICE QUESTION

Second Shipyard Cochin

+

S.N.Q. 1. Shri A. K. Gopalan:
Shri P. Kunhan:
Shri Warior:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Mohammed Koya:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Daljit Singh:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri P. Venkatasubbiah:
Shri Ravindra Varma:
Shri M. K. Kumaran:
Shri D. C. Sharma:
Shri Imbichibava:
Shri Nambiar:
Dr. Saradish Roy:
Shri Laxmi Dass:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether Government gave an assurance in Parliament that Cochin Shipyard would be included in the Third Plan;

(b) whether the project report has been finalised;

(c) if so, when the project is likely to be completed; and

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, the reasons for the delay?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha): (a) The Cochin Shipyard was included in the Third Five Year Plan amongst projects foreign exchange for which was yet to be arranged.

(b) to (d). The Project Report has been received from the technical consultants and is under scrutiny by a technical committee. The recommendations of the technical committee are expected to be received by the government very shortly. Government will take expeditious decisions soon after the receipt of these recommendations.

Shri A. K. Gopalan: As far as the first part of the Question is concerned, no answer is given. My question is:

> "(a) whether Government gave an assurance in Parliament that Cochin Shipyard would be included in the Third Plan;"

I put that question because in this Parliament, in the Second Lok Sabha, there was an adjournment motion moved by me. It was not taken up, though admitted, because the required number was not there. Then, an assurance was given by the then Transport Minister that this will be taken up in the Third Plan. That assurance was given in the Parliament. My question was whether the Government gave an assurance in Parliament that the Cochin Shipyard would be included in the Third Plan. No answer is given to that.

Sir, yesterday, they were unprepared and today the Minister is not here. There was an assurance in Parliament that this will be included in the Third Plan.

Shri C. M. Poonacha: There is no record to say that there was an assurance given in Parliament..... (*Interruptions*).

Shrimati Renu Chakravartty: No record?

Shri C. M. Poonacha: May I complete my answer?

Mr. Speaker: Order, order.